

समक्ष आईएस तिवाना, न्यायमूर्ति

हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़, - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ, चंडीगढ़ और अन्य, - प्रतिवादी।

1985 की सिविल रिट याचिका संख्या 2249

31 मार्च 1986

बोनस भुगतान अधिनियम (1965 का XXI) - धारा 32 (iv) - हरियाणा हाउसिंग बोर्ड अधिनियम (1971 का XX) - धारा 3(3), 7, 11, 18, 20 और 23 - सामान्य खंड अधिनियम (1897 का X) - धारा 3(31) - हरियाणा हाउसिंग बोर्ड - क्या वह बोनस अधिनियम की धारा 32 (iv) के संदर्भ में खुद को स्थानीय प्राधिकारी कह सकता है - क्या धारा में परिभाषित स्थानीय प्राधिकारी के लक्षण हैं सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3(31) - बोर्ड के कर्मचारी - चाहे बोनस के भुगतान के हकदार हों।

अभिनिर्धारित कि धारा 3(3) का वाचन। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1971 से पता चलता है कि बोर्ड को एक स्थानीय प्राधिकारी माना जाता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को कुछ समझा जाता है, तो एकमात्र अर्थ संभव होता है जबकि वह वास्तव में कुछ नहीं होता है। फिर, इस प्रावधान के अनुसार, बोर्ड को केवल हाउसिंग बोर्ड अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण माना जाना चाहिए, न कि भुगतान की धारा 32(iv) सहित किसी अन्य अधिनियम के प्रयोजनों के लिए। इस प्रकार स्पष्ट रूप से हाउसिंग बोर्ड को बोनस अधिनियम की धारा 32 (iv) के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकरण नहीं माना जा सकता है।

(पैरा 3)

अभिनिर्धारित कि हाउसिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 7, 11, 18, 20 और 23 की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि बोर्ड एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर है और इसके पास संपत्ति अधिग्रहण, धारण, प्रशासन और हस्तांतरण की शक्ति भी है। और उसके नाम पर अनुबंध में प्रवेश करने के लिए और उस नाम पर मुकदमा किया जा सकता है या मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसमें एक अध्यक्ष और इतनी संख्या में सदस्य होते हैं, लेकिन बारह से अधिक और छह से कम नहीं, जितनी राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है। जहां तक बोर्ड के संविधान का सवाल है, इसमें क्षेत्र के निवासियों के चुनाव या प्रतिनिधित्व का कोई तत्व नहीं है। यदि किसी कारण से बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा अपने विवेक से भरा जाएगा। जहां तक बोर्ड के कार्यों और कर्तव्यों का संबंध है, अधिनियम में कहा गया है कि राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, बोर्ड आवास योजनाओं के

निर्माण और कार्यान्वयन के लिए किसी भी क्षेत्र में व्यय कर सकता है और कार्य कर सकता है। समय-समय पर आवश्यक समझें या राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपा जाए। धारा 23 की आवश्यकता है बोर्ड को अपने कार्यक्रम, बजट और स्थापना कार्यक्रम तैयार करके राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होगा और राज्य सरकार इसे मंजूरी दे सकती है या ऐसे संशोधनों के साथ बोर्ड को अग्रेषित कर सकती है जो वह उचित समझे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत बोर्ड एक निकाय है जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा ही नियंत्रित और प्रबंधित है और इसका अस्तित्व और कामकाज पूरी तरह से सरकार द्वारा विनियमित है। बोर्ड का अपने फंड पर कोई स्वतंत्र नियंत्रण भी नहीं है। बोर्ड के खाते सालाना ऐसे व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षा योग्य होते हैं जिन्हें राज्य सरकार निर्देशित कर सकती है और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जानी है। बोर्ड के पास सामान्य धारा अधिनियम, 1897 की धारा 3(31) द्वारा परिकल्पित स्थानीय प्राधिकारी की शायद ही कोई विशेषताएँ हैं, और इस प्रकार इसके कर्मचारी हैं। बोनस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बोर्ड बोनस के भुगतान का हकदार है।

(पैरा 4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय मामले के रिकॉर्ड भेजने और उसका अवलोकन करने की कृपा करेगा :-

(1) 4 अप्रैल 1985 को प्रकाशित 6 मार्च 1985 के विवादित पुरस्कार को रद्द करते हुए सर्टिओरारी का उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। (अनुलग्नक पी/3);

(11) अनुबंधों की सत्यापित प्रतियां दाखिल करने से मुक्ति ;

(1111) लागत सहित याचिका की अनुमति दें।

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान , विवादित फैसले (अनुलग्नक पी/3) के संचालन पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर अग्निहोत्री और अधिवक्ता वीके वशिष्ठ ।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए राजिंदर सच्चर, वरिष्ठ अधिवक्ता, आरएल बत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता और जीसी टांगरी, अधिवक्ता ।

निर्णय

इस्तिवाना , न्यायमूर्ति

1. औद्योगिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के 6 मार्च, 1985 के फैसले को 1985 की इन दो सिविल रिट याचिकाओं संख्या 2249 और 3436 में चुनौती दी गई है - पहला नियोक्ता हरियाणा हाउसिंग बोर्ड द्वारा और दूसरा अपने कर्मचारी संघ द्वारा - हालांकि

विभिन्न आधारों पर और अलग-अलग सीमा पर चूंकि जहां तक तथ्यों का संबंध है, पार्टियां भिन्न नहीं हैं, इन्हें इस सामान्य निर्णय के माध्यम से निपटारा किया जा रहा है। पहली याचिका, यानी संख्या 2249 में विस्तृत तथ्य केवल इस निर्णय के प्रयोजनों के लिए विज्ञापित किए गए हैं।

2. यूनियन ने अपने चेयरमैन के माध्यम से हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को निम्नलिखित तीन मांगों को सूचीबद्ध करते हुए एक मांग नोटिस सौंपा:-

- (i) कर्मचारियों को वर्ष 1974-75, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के लिए 20 प्रतिशत बोनस का भुगतान किया जाए;
- (ii) उनमें से प्रत्येक को रुपये की दर से चिकित्सा लाभ का भुगतान किया जाएगा। 60/प्रति माह; और
- (iii) उनके रोजगार को नियंत्रित करने वाले नियम जल्द से जल्द बनाए जाएं।

चूंकि न तो बोर्ड ने किसी भी मांग को स्वीकार किया और न ही दोनों पक्षों के बीच सुलह हो सकी, इसलिए प्रशासन ने इस पर निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ का संदर्भ दिया। इसके बाद हुई सुनवाई के परिणामस्वरूप, ट्रिब्यूनल ने कर्मचारियों की पहली मांग स्वीकार कर ली और बोर्ड को उपरोक्त वर्षों के लिए उन्हें न्यूनतम 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान करने का निर्देश दिया, लेकिन उसने कोई भी स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने से इनकार कर दिया। अन्य दो मांगों पर, जैसा कि विवादित फैसले के अनुसार, कर्मचारियों के वकील द्वारा दबाव नहीं डाला गया था। जबकि बोर्ड इस आधार पर इस पुरस्कार का विरोध करता है कि यह बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (इसके बाद बोनस अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 32 के खंड (iv) के अर्थ के तहत एक स्थानीय प्राधिकरण है, यह किसी भी बोनस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, कर्मचारी इसे इस आधार पर वैध रूप से चुनौती देते हैं कि वे ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमत 8.33 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत की दर से बोनस के भुगतान के हकदार हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन याचिकाओं में सबसे पहले जिस बात को निपटाने की जरूरत है वह मुख्य कानूनी मुद्दा है कि क्या हरियाणा हाउसिंग बोर्ड बोनस अधिनियम की धारा 32 (iv) के तहत एक स्थानीय प्राधिकरण है। इस धारा का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"इस अधिनियम में कुछ भी इन पर लागू नहीं होगा

... ..

(iv) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग द्वारा या उसके अधिकार के तहत चलाए जाने वाले किसी भी उद्योग में लग प्रतिष्ठान द्वारा नियोजित कर्मचारी ।

इस प्रावधान का लाभ उठाने के लिए, बोर्ड की ओर से उठाया गया दोहरा तर्क यह है कि सबसे पहले हरियाणा हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1971 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (3) स्वयं अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निर्धारित करती है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुसार, बोर्ड को एक स्थानीय प्राधिकारी माना जाएगा , और दूसरी बात, भले ही अधिनियम के इस प्रावधान को मामले के तथ्यों के लिए अनुपयुक्त माना जाए, फिर भी इसमें एक स्थानीय प्राधिकरण के लक्षण मौजूद हैं। प्राधिकरण जैसा कि सामान्य खंड अधिनियम (1897 का 10) की धारा 3 (31) में परिभाषित किया गया है। हालाँकि, ट्रिब्यूनल के समक्ष बोर्ड द्वारा उठाई गई यह याचिका, मेरे विचार से, अच्छे कारणों से खारिज कर दी गई है।

3. वही प्रावधान, यानी, अधिनियम की धारा 3 (3), जिस पर बोर्ड के विद्वान वकील मेरे विचार से अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ भरोसा रखते हैं, तर्क को हरा देता है। यह उपधारा इस प्रकार है:

"इस अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड को एक स्थानीय प्राधिकरण माना जाएगा।"

तथ्य यह है कि बोर्ड को एक स्थानीय प्राधिकारी माना जाना चाहिए, इसका तात्पर्य यह है कि इस उपधारा की अनुपस्थिति में बोर्ड एक स्थानीय प्राधिकारी नहीं होता। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को कुछ "माना" जाता है, तो स्वीकार्य एकमात्र अर्थ यह है कि जबकि वह वास्तव में नहीं है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता होती है जैसे कि वह था । (**आयकर आयुक्त बॉम्बे प्रेसीडेंसी बनाम बॉम्बे ट्रस्ट कॉरपोरेशन, एआईआर 1930 प्रिवी काउंसिल 54** देखें)। फिर इस प्रावधान के अनुसार, बोर्ड को केवल अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक स्थानीय प्राधिकारी माना जाना चाहिए, न कि बोनस अधिनियम सहित किसी अन्य अधिनियम के प्रयोजनों के लिए। कुछ इसी तरह की स्थिति में मैसूर हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 3 (3) की व्याख्या करते समय, कौन सा प्रावधान समरूप है? अधिनियम की धारा 3 (3) के साथ, **मैसूर स्पन सिल्क मिल्स लिमिटेड , चन्नापटना बनाम मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड, आईएलआर 1951 मैसूर 434** के आधिकारिक परिसमापक में मैसूर उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित अनुसार राय दी :-

"तथ्य यह है कि बोर्ड को कुछ उद्देश्यों के लिए, अर्थात् मैसूर हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1955 और मैसूर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रयोजनों

के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण माना गया है, इस तर्क का पूर्ण उत्तर है कि यह जैसा कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में परिभाषित है, एक स्थानीय प्राधिकरण है। यदि वास्तव में बोर्ड एक स्थानीय प्राधिकरण है जैसा कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में परिभाषित है, तो विधानमंडल को मैसूर हाउसिंग बोर्ड की धारा 3 की उप-धारा (3) को अधिनियमित करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। अधिनियम, 1955 और इसमें उल्लेखित है कि बोर्ड को कुछ कृत्यों के प्रयोजन के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण माना जाएगा। यह कानूनी कल्पना है कि बोर्ड को मैसूर हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1955 और मैसूर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रयोजन के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण माना जाता है और इसका मतलब है कि यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्थानीय प्राधिकरण नहीं है। इसलिए, बोर्ड का दावा स्पष्ट रूप से अस्थिर है।"

मैं कानून के इस कथन से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ। **मैकबेथ एंड कंपनी बनाम चिस्लेट, 1910 एसी 220** में लोरबर्न एलसी के अनुसार, "यह संसद के अधिनियमों के निर्माण में एक नया आतंक होगा यदि हमें एक शब्द को अप्राकृतिक अर्थ तक सीमित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि कुछ अधिनियमों में जो निगमित या संदर्भित नहीं है, ऐसी व्याख्या केवल उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दी गई है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से बोर्ड को धारा 3 (3) के आलोक में बोनस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्यवाही करना एक स्थानीय प्राधिकरण नहीं माना जा सकता है।

4. जहां तक बोर्ड के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए मामले के अगले पहलू का सवाल है, इस संबंध में उनकी प्राथमिक निर्भरता **भारत संघ और अन्य बनाम आरसी जैन और अन्य, एआईआर 1981 सुप्रीम कोर्ट 951** में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। जिसमें बोनस अधिनियम की धारा 32 (iv) के संदर्भ में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद उनके आधिपत्य ने माना है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण एक स्थानीय प्राधिकरण है क्योंकि यह सभी सामान्य सुविधाओं से संपन्न है। सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित 'स्थानीय प्राधिकरण' की विशेषताएं इस निर्णय में, उनके आधिपत्य ने आगे कहा कि "धारा 3 (31) की भाषा की उचित और सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि एक प्राधिकरण, एक स्थानीय प्राधिकरण होने के लिए, एक नगरपालिका समिति, जिला के समान प्रकृति और चरित्र का होना चाहिए बंदरगाह आयुक्तों का बोर्ड या निकाय, इसलिए, नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड या निकाय बंदरगाह आयुक्तों की विशिष्ट विशेषताओं और विशेषताओं के, यदि सभी नहीं तो, बहुत सारे हैं, लेकिन एक आवश्यक विशेषता रखते हैं, अर्थात्, यह कानूनी रूप से हकदार है या सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण और प्रबंधन सौंपा गया है।" इस मामले की आगे जांच करते हुए कि क्या विशिष्ट गुण और विशेषताएँ हैं, जिनमें से सभी या कई नगरपालिका

समिति, जिला बोर्ड या बंदरगाह आयुक्तों का निकाय किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ साझा करते हैं, उनका प्रभुत्व निम्नानुसार व्यक्त किया गया है: -

- (i) इन प्राधिकरणों का कॉर्पोरेट निकायों के रूप में अलग कानूनी अस्तित्व होना चाहिए;
- (ii) वे केवल सरकारी एजेंसियां नहीं बल्कि कानूनी रूप से स्वतंत्र संस्थाएं होनी चाहिए;
- (iii) उन्हें एक परिभाषित क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, सामान्यतः, पूर्णतः या आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्षेत्र के निवासियों द्वारा चुना जाना चाहिए;
- (iv) उन्हें कुछ हद तक स्वायत्तता का आनंद लेना चाहिए, साथ ही उनके द्वारा प्रशासित क्षेत्र से संबंधित नीतिगत प्रश्न स्वयं तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वायत्तता पूर्ण नहीं हो सकती है और निर्भरता की डिग्री काफी भिन्न हो सकती है, लेकिन, स्वायत्तता का एक सराहनीय उपाय अवश्य होना चाहिए;
- (v) उन्हें कानून द्वारा ऐसे सरकारी कार्य और कर्तव्य सौंपे जाने चाहिए जो आमतौर पर नगर निकायों को सौंपे जाते हैं, जैसे कि इलाके के निवासियों को स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं, पानी और सीवरेज, नगर नियोजन और विकास, सड़कें, बाजार, परिवहन, सामाजिक कल्याण सेवाएँ आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने से जुड़े कार्य। मोटे तौर पर कहे तो उन्हें नागरिक कर्तव्यों और कार्यों का प्रदर्शन सौंपा जाना चाहिए जो अन्यथा सरकारी कर्तव्य और कार्य होंगे; और अंत में,
- (vi) शुल्क लगाकर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने की शक्ति होनी चाहिए। यह सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन के अतिरिक्त हो सकता है या उधार लेकर या अन्यथा प्राप्त किया जा सकता है। जो आवश्यक है वह यह है कि फंड का नियंत्रण या प्रबंधन प्राधिकरण के पास होना चाहिए।

ऊपर कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम के प्रावधानों की जांच करने पर, मैंने पाया कि संख्या (ii) से (v) में बताई गई स्थानीय प्राधिकारी के लिए जिम्मेदार विशेषताएँ या विशेषताएँ अब तक हरियाणा में पूरी तरह से गायब हैं। हाउसिंग बोर्ड चिंतित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुसार यह एक निगमित निकाय है जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर है और इसके पास चल या अचल संपत्ति के अधिग्रहण, धारण,

प्रशासन और हस्तांतरण और अनुबंध में प्रवेश करने की भी शक्ति है। इसके नाम पर और उस नाम पर मुकदमा किया जा सकता है फिर भी इसमें अध्यक्ष और इतनी संख्या में सदस्य होते हैं, लेकिन बारह से अधिक और छह से कम नहीं, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है। जहां तक बोर्ड के गठन का सवाल है, इसमें क्षेत्र के निवासियों के चुनाव या प्रतिनिधित्व का कोई तत्व नहीं है। बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य "राज्य सरकार की मर्जी तक" (धारा 7 की उपधारा (7ए)) पद धारण करते हैं। यदि किसी कारण, जैसे मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन, अयोग्यता या अन्यथा, बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यालय में कोई रिक्ति होती है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा अपने विवेक से भरा जाना है। बोर्ड के प्रत्येक सचिव को राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाना है जो वह उचित समझे (धारा 11)। बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी (धारा 18 की उप-धारा (1)) के बिना बीस लाख रुपये या उससे अधिक के व्यय वाले अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता है। जहां तक बोर्ड के कार्यों और कर्तव्यों का सवाल है, अधिनियम में कहा गया है (धारा 20) कि "राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, बोर्ड किसी भी क्षेत्र में व्यय कर सकता है और कार्य कर सकता है। ऐसी आवास योजनाएँ जिन्हें वह समय-समय पर आवश्यक समझे या जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी जाए।" धारा 23 के अनुसार बोर्ड को अपना वार्षिक आवास कार्यक्रम, बजट और स्थापना कार्यक्रम राज्य सरकार को तैयार करने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और बाद वाला कार्यक्रम, बजट और अधिकारियों और नौकरों के ठहरने के कार्यक्रम को मंजूरी दे सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियमों के तहत बोर्ड एक निकाय है जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा ही नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। इसका अस्तित्व और कामकाज पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा विनियमित है। यह कमोबेश काम करता है या कार्य करता है एक सरकार के रूप में। यह सच है कि अधिनियम के अध्याय VII के अनुसार बोर्ड के पास "हाउसिंग बोर्ड फंड" के रूप में जाना जाने वाला एक फंड है, लेकिन इसे कोई कर, दरें, शुल्क और शुल्क आदि लगाकर नहीं जुटाया जाता है। बल्कि यह मुख्य रूप से गठित है केंद्र या राज्य सरकारों या स्थानीय निकाय द्वारा अनुदान, दान या उपहार या बोर्ड द्वारा संपत्ति की बिक्री। बोर्ड के खाते ऐसे व्यक्तियों द्वारा वार्षिक रूप से ऑडिट किए जा सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार निर्देशित कर सकती है। ऑडिटर की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना है। इस प्रकार बोर्ड के पास अपनी निधियों का शायद ही कोई स्वतंत्र नियंत्रण या प्रबंधन है। मैं इस प्रकार संतुष्ट हूँ कि हाउसिंग बोर्ड के पास सामान्य धारा अधिनियम की धारा 3 (31) द्वारा परिकल्पित या उपर्युक्त निर्णय में उनके आधिपत्य द्वारा निर्दिष्ट, यानी, **आरसी जैन के मामले (सुप्रा)** के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण की शायद ही कोई विशेषता या विशेषताएं हैं। मेरे इस निष्कर्ष के सामने बोर्ड द्वारा दायर याचिका स्पष्ट रूप से विफल हो गई है और खारिज कर दी गई है।

5. जहां तक ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत दर से अधिक बोनस दर के लिए यूनियन के दावे (सीडब्ल्यूपी नंबर 3436 में) का सवाल है, तो मैंने पाया कि ट्रिब्यूनल ने बोर्ड द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ के बारे में विचाराधीन वर्षों के दौरान कोई स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। ट्रिब्यूनल द्वारा इस मामले का निष्कर्ष इस प्रकार निकाला गया है:-

"अब बोनस की मात्रा पर आते हैं, श्री बसूर ने वर्ष 1971-72 से 1977-78 तक बोर्ड के खातों के वार्षिक विवरण का उल्लेख किया है जो Ex. पी-2 से पी-8 हैं। उनके अनुसार बोर्ड ने भारी कमाई की थी ताकि कामगार कम से कम 20 प्रतिशत बोनस के हकदार हों। लेकिन मैं इस दलील से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। Ex. पी-2 से पी-8 के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिवादी का अधिकांश धन बोर्ड ऋणों की अग्रिम राशि के माध्यम से आया और प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया राशि उन अग्रिमों के कारण होती है, न कि मुनाफे के कारण। इसलिए, मेरे विचार में कामगार उनके द्वारा दावा किए गए वर्ष के लिए केवल 8.33 प्रतिशत के न्यूनतम बोनस के हकदार हैं और इससे अधिक नहीं, और प्रतिवादी बोर्ड कामगारों को इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।"

जाहिर तौर पर ट्रिब्यूनल ने बोर्ड द्वारा अर्जित लाभ की वास्तविक राशि का पता लगाने के लिए विवरण में नहीं गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इन कार्यवाहियों में, मैं संभवतः अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता या विचाराधीन वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा अर्जित लाभ के बारे में साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकता। इसलिए, इस याचिका में 8.33 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत की दर से बोनस देने के लिए यूनियन के दावे को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने किया है। जहां तक मामले के इस पहलू का संबंध है, मेरी राय में यह मामला नए सिरे से निर्णय के लिए ट्रिब्यूनल के पास भेजे जाने लायक है। इसलिए, मैं इस याचिका को इस हद तक स्वीकार करता हूं कि विवादित फैसले के पैराग्राफ 5 में दर्ज निष्कर्ष को खारिज कर दिया जाए और ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया जाए कि वह प्रश्नगत वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ की मात्रा को फिर से निर्धारित करे और फिर निर्णय ले। अगला सवाल यह है कि यूनियन द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारियों को किस दर पर बोनस का भुगतान किया जाना है। मैं तदनुसार ऑर्डर करता हूं। स्पष्टता के लिए, यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसा निर्णय लेने तक, कर्मचारियों को ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशित दर पर बोनस का भुगतान जारी रखा जाएगा।

6. किसी भी याचिका में लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा